(ग) क्या सरकार उपर्युक्त वर्ग के व्यक्तियों द्वारा उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक विकास निगम और वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से संतुष्ट है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा उद्योग स्थापित किए जाने संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। किन्तु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) के कार्यकलापों से अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला कामगारों को लाभ होता है। इस समय के० वी० आई० सी० से लाभान्वित होने वाले कुल लाभग्राहियों में से 30.35 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

इसके अलावा, पिछड़े जिलों विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी वाले जिलों के लिये के० वी० आई० सी० ने भी विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विकासार्थ इस विभाग के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) कई योजनाएं चला रहा है जैसे कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम, प्रबंध प्रशिक्षण, प्रधान मंत्री रोजगार योजना और शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्वरोजगार योजना (एस ई ई वाई यू)। इन योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के भी लाभग्राही लोगों हेतु विशिष्ट आरक्षण हैं।

(ख) और (ग) भाग (ख) तथा (ग) के संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

Dbfcmstment of Nine Psu.

1425 : SHRI CHATURANAN MISHRA :
SHRI GAYA SINGH :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to divest its equity holdings in nine important central public sector undertakings upto 49 per cent ;and

(b) if so, the names of these PSUs and the total amount of money expected to be raised through this disinvestment programme and the reasons to take such a decision ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रुग्न औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि

1426. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं की घोषणा के बावजूद देश में रुग्ण औद्योगिक इकाईयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो मार्च, 1991, मार्च 1992 और मार्च, 1993 में देश में रुग्ण औद्योगिक इकाईयों की संख्या कितनी थी, और

(ग) उपरोक्त वर्षों के दौरान बड़े, मध्यम तथा छोटे रुग्ण उद्योगों की अलग-अलग संख्या क्या थी तथा इन उद्योगों में स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संस्थानों के ऋण के रूप में पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) देश में बैंकों की सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम-उपलब्ध आंकड़े मार्च, 1992 के अंत तक के हैं।